Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

(भाग–1)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM28

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था

(भाग–1)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

1.	अर्थव्यवस्था : एक परिचय	5–22
	1.1 अर्थशास्त्र की प्रमुख शाखाएँ	6
	1.2 अर्थव्यवस्था के प्रकार	7
	1.3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	9
	1.4 आय का चक्रीय प्रवाह	12
	1.5 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ	15
2.	राष्ट्रीय आय	23–47
	2.1 राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ एवं अंतर्संबंध	29
	2.2 घरेलू आय एवं राष्ट्रीय आय	32
	2.3 शब्दावली	36
	2.4 आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास	37
	2.5 2018–19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति : एक समष्टि परिदृश्य	40
3.	मुद्रास्फीति	48–70
	3.1 मुद्रास्फीति के कारण	48
	3.2 मुद्रास्फीति के प्रकार	49
	3.3 मुद्रास्फीति की गणना	53
	3.4 कीमत सूचकांक विधि	53
	3.5 मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर प्रभाव	61
	3.6 भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति	64
	3.7 मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली	67
4.	आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	71–121
	4.1 भारत की विकास रणनीति	71
	4.2 उदारीकरण	79
	4.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	97

5.	गरीबी	122–143
	5.1 गरीबी के प्रकार	122
	5.2 भारत में गरीबी	126
	5.3 गरीबी को दूर करने के उपाय	130
	5.4 कुछ महत्त्वपूर्ण सूचकांक	133
6.	बेरोज़गारी	144–181
	6.1 भारत में बेरोज़गारी	145
	6.2 छत्तीसगढ़ में आय एवं रोज़गार के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन	155
	6.3 वैश्वीकरण और रोज़गार	159
	6.4 भारत में बेरोज़गारी दूर करने के मुख्य कार्यक्रम	160
	6.5 छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास एवं रोज़गार	165
7.	जनांकिकीय	182–191
	7.1 जनसंख्या	184
	7.2 जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत	184
	7.3 कार्यशील जनसंख्या एवं जनांकिकीय लाभांश	186
	7.4 जनसंख्या पिरामिड	187
	7.5 जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द	187
8.	आयोजन	192–247
	8.1 आयोजन के प्रकार	193
	8.2 भारत में आयोजन	196
	8.3 भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ	202
	8.4 सरकार की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम	215
	8.5 नीति आयोग	222
9.	कर संरचना	248–292
	9.1 कर के उद्देश्य	248
	9.2 कराधान की प्रणाली	250
	9.3 शब्दावली	251
	9.4 भारतीय कर व्यवस्था	258
	9.5 कर सुधार	267

अध्याय
1

अर्थव्यवस्था : एक परिचय
(Economy : An Introduction)

अर्थव्यवस्था क्या है? *(What is Economy?)*

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (Socio-economic Conditions) में सुधार करने के उद्देश्य से, उपलब्ध संसाधनों (Available Resources) का समुचित नियोजन (Appropriate Planning) करते हुए अर्थ (Money) को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। वास्तव में 'अर्थव्यवस्था' शब्द अधूरा ही रहेगा जब तक कि इसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र (Economics) का गतिशील (Dynamic) चित्र है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होता है। यदि हम कहते हैं- 'समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था' तो इसका तात्पर्य होता है- वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन।

अर्थशास्त्र क्या है? *(What is Economics?)*

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है, जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र में संबंध *(Relation between Economy and Economics)*

अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं।
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है।
- निर्माण एवं विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खन्न प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं।
- एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी।
- व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत हाट्रे महोदय ने दिया था।
- पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है।
- मानव विकास रिपोर्ट, 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा।
- वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.554 था।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में राज्य में कोरबा ज़िला शीर्ष पर है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानव विकास रिपोर्ट, 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन-सा है? **CGPCS (Pre) 2018**
   (a) स्विट्ज़रलैंड (b) जर्मनी
   (c) आयरलैंड (d) नॉर्वे
2. छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? **CGPCS (Pre) 2017**
   (a) कोरबा (b) महासमुंद
   (c) दुर्ग (d) रायपुर
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से दर्शाता समझता है कि भारत अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है? **CGPCS (Pre) 2017**
   1. आय का असमान वितरण
   2. उच्च निर्भरता दर
   3. राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर
   4. बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन

   नीचे दिये गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिये:
   (a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 4
   (c) 1 और 4 (d) उपरोक्त सभी
   (e) इनमें से कोई नहीं
4. वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य था: **CGPCS (Pre) 2014**
   (a) 0.387
   (b) 0.454
   (c) 0.416
   (d) 0.554
   (e) इनमें से कोई नहीं
5. वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट (ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट) कौन प्रकाशित करता है?
   (a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
   (b) संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूनाइटेड नेशंस कॉन्फरेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट)
   (c) विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम)
   (d) विश्व बैंक
6. 'व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक '(Ease of Doing Business Index)' में भारत की रैंकिंग समाचार-पत्रों में कभी-कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है?
   (a) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
   (b) विश्व आर्थिक मंच
   (c) विश्व बैंक
   (d) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिये स्वतंत्र हैं जिनकी मांग अधिक है।
   2. उपभोक्ता अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिये स्वतंत्र होते हैं।

   उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ हैं?
   (a) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
   (b) समाजवादी अर्थव्यवस्था
   (c) मिश्रित अर्थव्यवस्था
   (d) अल्पविकसित अर्थव्यवस्था
8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. मिश्रित कीमत क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय बाज़ार द्वारा लिये जाते हैं।
   2. भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2
9. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प 'संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ' (Transitional economics) है?
   (a) पहली दुनिया के देश
   (b) दूसरी दुनिया के देश
   (c) तीसरी दुनिया के देश
   (d) चौथी दुनिया के देश
10. आभूषण (Jewellery) उदाहरण है:
    (a) भौतिक पूंजी का
    (b) वित्तीय पूंजी का
    (c) बौद्धिक पूंजी का
    (d) कलात्मक बौद्धिक पूंजी का
11. निम्नलिखित में से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है:
    (a) विनिर्माण
    (b) निर्माण
    (c) खनन एवं उत्खनन
    (d) जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति
12. समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है:
    (a) योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण।
    (b) श्रम-विभाजन और विनिमय।
    (c) सरकार अंतिम निर्णायक के रूप में।
    (d) निजी स्वामित्व की धारणा नहीं।
13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    1. विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में बाज़ार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है।
    2. नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है।
    3. प्राथमिक वस्तुओं में परिवर्तन से नई वस्तुओं का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र करता है, जैसे- खनन एवं उत्खनन।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?
    (a) केवल 2 (b) केवल 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

1. (d) 2. (a) 3. (b) 4. (d) 5. (c) 6. (c) 7. (a) 8. (d) 9. (b) 10. (b)
11. (c) 12. (b) 13. (c)

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है?
2. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
3. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को बतलाइये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहे आधुनिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों को बतलाइये। **CGPCS (Mains) 2016**
2. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें।
3. व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. अर्थव्यवस्था क्या है? इसकी आर्थिक क्रिया एवं प्रकारों को समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित करते हुए विश्लेषण करें।
2. उत्पादन के कारकों व क्षेत्रों को स्पष्ट करते हुए यह स्पष्ट करें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्यों महत्त्वपूर्ण है?
3. आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? इसके द्वारा हमारी वित्तीय व्यवस्था कैसे प्रभावित होती है? स्पष्ट करें।

अध्याय
2

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक *(Factors Affecting National Income)*

- **प्राकृतिक संसाधन:** किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, क्षेत्र और मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, खनिज एवं तेल संसाधन, अच्छी जलवायु, अच्छी नदी प्रणाली आदि सम्मिलित हैं। उच्च राष्ट्रीय आय के लिये प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता एवं उनका गुणवत्तायुक्त होना अनिवार्य है। लेकिन अच्छे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ही उच्च राष्ट्रीय आय के लिये आवश्यक शर्त नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, परंतु उन्होंने उत्साहवर्द्धक आर्थिक विकास प्राप्त किया है। उदाहरण के लिये स्विट्ज़रलैंड के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं और न ही भौतिक पर्यावरण अनुकूल है, फिर भी उस राष्ट्र ने काफी उन्नति की है और वहाँ की प्रति व्यक्ति आय तथा संपत्ति अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना में कम नहीं है।
- **पूंजी निर्माण:** किसी भी अर्थव्यवस्था में उच्च राष्ट्रीय आय या आर्थिक संवृद्धि के लिये पूंजी निर्माण एक महत्त्वपूर्ण कारक है। प्राय: जब राष्ट्रीय आय का एक बड़ा अंश बचाकर पुन: निवेश किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज़ होती है। वस्तुत: पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी समुदाय की बचतों को पूंजीगत वस्तुओं, जैसे- प्लांट, भूमि, मशीनों के निवेश के लिये प्रयोग किया जाता है, जिससे देश की उत्पादन क्षमता तथा श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है तथा देश में वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित किया जाता है। पूंजी निर्माण राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि लाता है। जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर उच्च रही है, उन देशों ने अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक संवृद्धि प्राप्त की है। भारत में 1970 के दशक में पूंजी निर्माण की दर सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 15 प्रतिशत थी, जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजी निर्माण की दर लगभग 30 प्रतिशत से अधिक है।
- **पूंजी उत्पाद अनुपात:** उत्पादन की प्रति इकाई पर लगने वाली पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के लिये यदि 1 इकाई उत्पादन पर पूंजी की 3 इकाई लगे तो कहा जाता है कि पूंजी उत्पाद अनुपात 3:1 है। इसके दो रूप हो सकते हैं:
  - औसत पूंजी उत्पाद अनुपात
  - वर्द्धमान पूंजी उत्पाद अनुपात [Incremental Capital Output Ratio (ICOR)]

  किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ICOR का कम होना लाभदायक और प्रगतिशील होता है। ऐसी स्थिति में कम पूंजी एवं निवेश से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।
- **कृषि का विक्रय अधिशेष:** किसी देश के आर्थिक विकास के लिये कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि महत्त्वपूर्ण कारक है, परंतु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है कृषि के विक्रय अधिशेष में वृद्धि। इस कृषि के विक्रय योग्य अधिशेष पर ही शहरी क्षेत्रों के लोगों का गुज़र-बसर होता है। ध्यातव्य है कि जैसे-जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकास पथ पर आगे बढ़ती है, शहरी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जाता है, जिससे खाद्यान्नों की मांग बढ़ती जाती है। इस मांग को पूरा करना भी आवश्यक है, अन्यथा विकास प्रक्रिया में बाधा आएगी।

अध्याय
3

मुद्रास्फीति (Inflation)

'मुद्रास्फीति' से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह 'मुद्रास्फीति की अवस्था' कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमज़ोर होना ही मुद्रास्फीति की अवस्था है। मुद्रास्फीति के कारण आगतों की कीमत तथा ब्याज दर में वृद्धि होती है, जिस कारण निवेश की लागत में भी वृद्धि होती है, जो कि संवृद्धि की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में जानी जाती है।

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात् वस्तुओं-सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत् रूप से बढ़ती हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे 'मुद्रास्फीति' कहा जाता है। यह व्यापार चक्रों का एक भाग है। अस्थायी तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता। मंदी के दौरान सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी को स्फीतिकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक नहीं होते हैं।

$$\text{वस्तु की मांग} \uparrow + \text{वस्तु की आपूर्ति} \downarrow \Rightarrow \text{वस्तु की कीमत} \uparrow (\text{मुद्रास्फीति})$$

विकास दर एवं मुद्रास्फीति के बीच एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि यदि विकास दर बढ़ानी है तो इसके लिये अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन बढ़ाने के लिये निवेश को बढ़ाना होगा। चूँकि, निवेश एवं ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध होता है, इसलिये निवेश तभी बढ़ेगा, जब ब्याज दर को घटाया जाए, परंतु यदि ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश एवं विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की ऊँची दर होने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दर को बढ़ाना नहीं चाहता।

धारणीय मुद्रास्फीति *(Sustainable Inflation)*

किसी भी अर्थव्यवस्था में आवश्यक विकास दर को बनाए रखने के लिये एक निश्चित सीमा में मुद्रास्फीति की आवश्यकता बनी रहती है। धारणीय मुद्रास्फीति इसी संकल्पना पर आधारित है।

धारणीय मुद्रास्फीति का अर्थ मुद्रास्फीति की ऐसी दर से होता है, जिस पर अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है तथा आम लोगों को भी कोई विशेष समस्या नहीं होती। भारत जैसे विकासशील देशों के लिये लगभग 5-6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति को 'धारणीय मुद्रास्फीति' कहा जाता है, जबकि विकसित देशों के लिये लगभग 2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति धारणीय मानी जाती है।

3.1 मुद्रास्फीति के कारण *(Causes of Inflation)*

मांग प्रेरित मुद्रास्फीति *(Demand-Pull Inflation)*

जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है तो उसे 'मांग प्रेरित मुद्रास्फीति' कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्न कारणों से आ सकती है- लोगों की आय बढ़ने, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि कारणों से मांग बढ़ने से।

अध्याय
4

आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (Effects of Economic Reforms and Liberalization on the Indian Economy)

आज़ादी के पश्चात् भारत को विरासत में एक पिछड़ी औद्योगिक व्यवस्था मिली, जिसका पुनरुद्धार कर तीव्रता से विकास करना अपरिहार्य था। औद्योगिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में सुधार के लिये विभिन्न प्रयास किये, जिसके फलस्वरूप पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आज़ादी के पश्चात् विभिन्न प्रकार की औद्योगिक संस्थाएँ अनेक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रही थीं। हालाँकि उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली संस्थाएँ कुछ ही थीं। इनमें भी पूंजीगत उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली संस्थाएँ बेहद कम थीं। 1948 में भारत सरकार ने एक औद्योगिक नीति को अपनाया, जिसका केंद्रीय उद्देश्य आधुनिक औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात करना था। इसके लिये 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई तत्पश्चात् 1951 में औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम लाया गया। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन के लिये विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए। राज्य स्तर पर राज्य वित्त सहकारिता अधिनियम, 1951 लाया गया जो आज भी लागू है। इन सभी प्रयासों द्वारा भारत में औद्योगिक प्रगति का सूत्रपात किया गया।

4.1 भारत की विकास रणनीति *(The Development Strategy of India)*

स्वतंत्रता के पश्चात् शुरुआती वर्षों में भारत की विकास रणनीति मुख्यत: चार तत्त्वों पर केंद्रित थी-

1. आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल।
2. केंद्रीकृत निवेश योजना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर बल।
4. आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात पर कम बल देकर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

संयुक्त रूप से इन्हें नेहरूवादी विकास मॉडल माना जाता था। नेहरूवादी मॉडल ने भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आधार रखने एवं कई बार सूखा पड़ने, अंतर्राष्ट्रीय तेल-मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने तथा लगभग तीन युद्ध होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाए रखा। हालाँकि 1960 के दशक से यह व्यवस्था अत्यधिक नौकरशाही तथा अति नियमन वाली अर्थव्यवस्था में बदल गई। इससे परमिट-लाइसेंस का उदय हुआ। इस परमिट-लाइसेंस व्यवस्था के अवांछित परिणाम भी देखने को मिले, जैसे-

- प्रशुल्क एवं कोटा के माध्यम से विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षित होने के कारण उच्च लागत वाले घरेलू उद्योगों का विकास हुआ।
- मौद्रिक नीति पर राजकोषीय प्रभुत्व, जिसके कारण राजकोषीय अनियमितता को बढ़ावा मिला।

आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आग्रह के कारण तथा आंशिक रूप से तत्कालीन नीतियों से निराश होने के कारण भारत ने कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया। इस ऐतिहासिक कदम के अंतर्गत सरकार ने तत्कालीन आर्थिक नीतियों से नाता तोड़ने तथा महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया। इस संकट को अवसर में बदलने के लिये आर्थिक नीतियों की विषय-वस्तु तथा उपागम (Content and approach) में कुछ महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गए।

अध्याय
5

गरीबी (Poverty)

गरीबी वह स्थिति है, जब लोग भोजन, वस्त्र एवं आवास या आश्रय संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है।

5.1 गरीबी के प्रकार *(Types of Poverty)*

सामान्य रूप से गरीबी दो प्रकार की होती है-

1. **निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty):** निरपेक्ष गरीबी गंभीर अभाव (Severe deprivation) की स्थिति है, जिसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं, जैसे– भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा तथा सूचना का अभाव होता है। भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिये गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह रेखा है, जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है, जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है, उन्हें निर्धन माना जाता है। यह केवल आय पर ही नहीं बल्कि सेवाओं की पहुँच पर भी निर्भर करती है। इस तरह की गरीबी मुख्यतः अल्पविकसित तथा विकासशील देशों में दिखाई देती है।
2. **सापेक्षिक गरीबी (Relative Poverty):** समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को 'सापेक्षिक गरीबी' कहते हैं अर्थात् सापेक्षिक गरीबी तब देखने को मिलती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। वे सामान्य जीवन जीने तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये संघर्ष करते हैं। सापेक्षिक गरीबी देश के अनुसार बहुसंख्यकों के जीवन स्तर के अनुसार बदलती रहती है। हालाँकि यह निरपेक्ष गरीबी की तरह तीव्र नहीं है, लेकिन यह काफी गंभीर एवं हानिकारक है। जिस समाज में पूर्ण समानता होती है, उस समाज में सापेक्षिक गरीबी नहीं होती है, किंतु विश्व में कहीं भी ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अतः विश्व के हर देश में सापेक्षिक गरीबी पाई जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गरीबी विकल्पों एवं अवसरों से वंचित करना एवं मानव गरिमा का उल्लंघन है। गरीबी के कारण व्यक्ति समाज में प्रभावी रूप से सहभागिता नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य परिवार के लिये भोजन एवं वस्त्र जुटाने में अक्षमता से है। गरीब व्यक्ति स्कूल या अस्पताल जाने में सक्षम नहीं होता है। उसके पास रोज़गार करने, खाद्यान्न उपजाने या रहने के लिये ज़मीन का अभाव होता है। उसकी क्रेडिट तक पहुँच नहीं होती है। गरीबी से तात्पर्य व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदायों की असुरक्षा, शक्तिहीनता तथा बहिष्करण से है।

कुल मिलाकर गरीबी कई रूपों में दिखाई दे सकती है। इसमें सतत् आजीविका, भूख एवं कुपोषण को समाप्त करने वाली आय एवं उत्पादक संसाधनों का अभाव पाया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव होता है। बीमारियों के कारण अस्वस्थता तथा मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत आवास विहीनता या अपर्याप्त आवास, असुरक्षित पर्यावरण, सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्करण देखने को मिलता है। इसे निर्णय-निर्माण तथा नागरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में सहभागिता के अभाव के रूप में भी देखा जाता है। यह सभी देशों में देखने को मिलती है। विकासशील देशों तथा विकसित देशों के कुछ क्षेत्रों में भी व्यापक गरीबी दिखाई देती है। आर्थिक मंदी के कारण आजीविका खोने, संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक गरीबी पैदा होती है। कम मज़दूरी वाले कामगारों में भी गरीबी पाई जाती है। पारिवारिक सहायता, सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से बाहर हो गए लोगों में भी गरीबी पाई जाती है।

अध्याय
6

बेरोज़गारी (Unemployment)

बेरोज़गारी वह स्थिति है, जब एक व्यक्ति सक्रियता से रोज़गार की खोज करता है, लेकिन वह काम पाने में विफल रहता है। बेरोज़गारी को सामान्यत: बेरोज़गारी दर के रूप में मापा जाता है। बेरोज़गारी दर, बेरोज़गार व्यक्तियों की वह संख्या है, जो श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है।

एक व्यक्ति को बेरोज़गार तब माना जाता है, जब वह प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिये तैयार तथा इच्छुक है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता तब ऐसे व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' तथा ऐसी समस्या को 'बेरोज़गारी की समस्या' कहा जाता है।

भारत में बेरोज़गारी के लक्षण *(Features of Unemployment in India)*

- सामान्यत: हम लोग उस व्यक्ति को बेरोज़गार मानते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है या जिसे कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन यह पूर्णत: नहीं बल्कि अंशत: ही सही है। यह बात ज़्यादातर उन व्यक्तियों के मामले में सही है,जो शिक्षित हैं और काम पाने में सक्षम नहीं हैं या जो काम की तलाश में शहरों में आते हैं।
- इस तरह हम एक बड़े वर्ग या अधिसंख्यक व्यक्ति जो खेती के कार्य से जुड़े हैं और जिन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें रोज़गार करने वाले व्यक्तियों में से बाहर कर देते हैं। उदाहरण के लिये, जो व्यक्ति एक छोटे भूखंड का मालिक है और जो खेती करता है, वह भी रोज़गाररत है, जबकि उसे भी वेतन या मज़दूरी नहीं मिलती है।

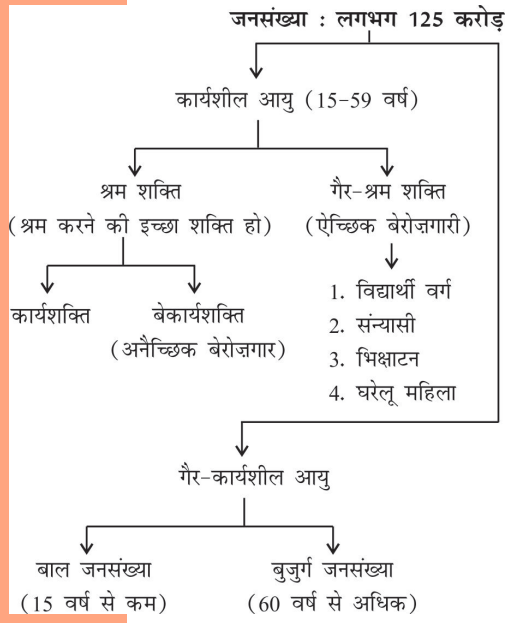

- इसी तरह देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसे उसके कार्य के बदले किसी तरह का वेतन या मज़दूरी नहीं मिलती है। इनमें किसान, छोटे दुकानदार, कारीगर, टैक्सी ड्राइवर, मैकेनिक, छोटे एवं बड़े उद्योगपति आदि शामिल हैं, जबकि इन्हें भी काम में लगे हुए व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन व्यक्तियों के अलावा वेतन प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्तियों को नियोजित या रोज़गाररत व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि काम के बदले वे वेतन या वस्तु प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं, वे बेरोज़गार हैं। अगली समस्या बेरोज़गार व्यक्तियों की पहचान करने से जुड़ी है।
- सामान्य रूप में भारत में 15–59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय माना जाता है। अन्य शब्दों में इस आयु वर्ग के व्यक्तियों में काम करने या नियोजित होने की क्षमता है। इस तरह इस आयु वर्ग (15–59 वर्ष) के जो व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं, उन्हें बेरोज़गार माना जाता है, लेकिन यह परिकल्पना भी पूरी तरह सही नहीं है। इस आयु वर्ग में कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो नियोजित होना ही नहीं चाहते हैं। ये वैसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं और वे स्वयं रोज़गार करना नहीं चाहते हैं। हाल के दिनों तक अधिसंख्यक महिलाओं, विशेषकर विवाहित महिलाओं को इसी श्रेणी का समझा जाता था, क्योंकि वे घरेलू कार्य करती हैं।

अध्याय
7

जनांकिकीय (Demographic)

भारत की जनांकिकीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- अधिक जनसंख्या
- ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता
- उच्च वृद्धि दर
- निम्न लिंगानुपात
- आत्मनिर्भरता की स्थिति
- नृजातीय विविधता
- वृद्धि के परिणाम

अधिक जनसंख्या *(Excess population)*

किसी देश में अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो उसके अधिकतम (संपूर्ण) संसाधनों का अधिकतम दोहन कर सकने वाली न्यूनतम जनसंख्या हो। इस दृष्टि से भारत की स्थिति के संबंध में यह माना गया है कि यद्यपि अभी तक हमने संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं किया है, किंतु उनकी तुलना में जनसंख्या की अधिकता निर्विवादित रूप से प्राप्त कर ली है। दुनिया भर के क्षेत्रफल व व्यापार में भारत का जितना हिस्सा है उससे कई गुणा अधिक हिस्सा जनसंख्या का है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025-2050 के बीच भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 1% पर सीमित हो गई है जबकि भारत की 2011 में औसत वार्षिक जनसंख्या दर 1.64% है। ऐसी स्थिति में भारत की जनसंख्या 34 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी जबकि चीन की 60 वर्षों में दोगुनी होगी। जनसंख्या की अधिकता से आने वाले वर्षों में भीड़-भाड़, अपराध, महँगाई, आवास आदि की समस्याएँ तेज़ी से बढ़ सकती हैं।

कारण

देश में जनसंख्या अधिक होने के कारणों में-

- मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर का अधिक होना।
- प्राय: कम उम्र में विवाह करने की सामाजिक मान्यता।
- धार्मिक अंधविश्वास तथा धर्मों का जनसंख्या नियंत्रण में सहायक न होना।
- निरक्षरता की अधिकता, जिस कारण जनसंख्या कम करने की चेतना का अभाव होना।
- पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पुत्र प्राप्ति की प्रबल चाह।
- आर्थिक विकास की कमी।
- जीवन प्रत्याशा का धीरे-धीरे उच्च स्तर पर आना।
- जनसंख्या नियंत्रण के लिये उपयुक्त वैज्ञानिक सुविधाओं का अभाव।
- जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के संबंध में आम लोगों तक जानकारी का न पहुँच पाना।
- निम्न वर्गों के लिये बच्चों का अर्जक के रूप में होना।
- महिलाओं में अविवेकपूर्ण धारणा का होना।
- ग्रामीण महिलाओं को यह विश्वास नहीं होना कि उनका बच्चा जीवित रहेगा ही।
- अधिक बच्चों को जन्म देने में विश्वास रखना एवं कृषि पर निर्भरता आदि प्रमुख हैं।

अध्याय
8

आयोजन (Planning)

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग (Optimum Utilization) सुनिश्चित हो सके। साथ ही दीर्घकालिक निरंतरता (Long-Term Continuity) सुनिश्चित हो सके, आर्थिक आयोजन कहलाता है। इसे आयोजना, आर्थिक नियोजन एवं योजना-निर्माण आदि नामों से भी जाना जाता है।

कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में आर्थिक नियोजन द्वारा समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। लगभग 200 वर्षों के अंग्रेज़ी शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को जान-बूझकर अल्पविकसित बनाने के उद्देश्य से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के साथ इस तरह जोड़ दिया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गई थी। देश के औपनिवेशिक शोषण (Colonial Exploitation) और अल्पविकास की वजह से जो आर्थिक समस्याएँ पैदा हुईं, उनमें बेरोज़गारी और गरीबी (Poverty) सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अत: बाज़ार-तंत्र पर निर्भर रहकर न तो देश की समस्याओं को हल किया जा सकता था और न ही एक लंबे समय से रुकी हुई विकास-प्रक्रिया को फिर से आरंभ किया जा सकता था। अत: भारत के नीति-निर्माताओं ने प्रारंभ से ही आर्थिक नियोजन का समर्थन किया। इसी पृष्ठभूमि में भारत में सन् 1951 में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया आरंभ हुई।

आयोजन की आवश्यकता क्यों? *(Why Need Planning?)*

ऐसे अनेक कारण थे, जिन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को जन्म दिया। इनमें प्रमुख थे: व्यापक गरीबी, बेरोज़गारी, निम्न उपभोग स्तर, गरिमाहीन जीवन-शैली, उद्योगों का अभाव, व्यापार का अभाव, कौशल का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव आदि। आयोजन की प्रक्रिया को समझने के लिये पहले हमें उत्पादन ढाँचे को समझना होगा। उत्पादन ढाँचे का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है:

- **उत्पादन संरचना के आधार पर (On the basis of Production Structure):** किसी देश या किसी क्षेत्र-विशेष के कुल उत्पादन में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत अंशदान की संरचना को उत्पादन संरचना कहा जाता है। इस संरचना के आधार पर इसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं:
  - **विकसित उत्पादन संरचना (Developed Production Structure):** यदि किसी देश की उत्पादन संरचना में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत अंश न्यूनतम, उद्योग का उससे अधिक और सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक हो तो उसकी उत्पादन संरचना को विकसित उत्पादन संरचना कहा जाता है।
  - **अविकसित उत्पादन संरचना (Undeveloped Production Structure):** यदि किसी देश की उत्पादन संरचना में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत अंश न्यूनतम, उद्योग का उससे अधिक और कृषि क्षेत्र का अंश सर्वाधिक हो तो उसकी उत्पादन संरचना को अविकसित उत्पादन संरचना कहा जाता है।
  - **विकासशील उत्पादन संरचना (Developing Production Structure):** यदि किसी देश की उत्पादन संरचना में कृषि का प्रतिशत अंश निरंतर कम होता जा रहा हो तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का प्रतिशत अंश बढ़ता जा रहा हो तो उसे विकासशील उत्पादन संरचना कहा जाता है।
- **पेशागत संरचना के आधार पर (On the Basis of Professional Structure):** किसी देश या किसी क्षेत्र-विशेष के कुल रोज़गार में उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत अंशदान की संरचना को **पेशागत संरचना** (Professional Structure) कहा जाता है। इस संरचना के आधार पर इसे तीन आधारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - **विकसित पेशागत संरचना (Developed Professional Structure):** यदि किसी देश के कुल उपलब्ध रोज़गार में कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोज़गार का प्रतिशत अंश न्यूनतम हो और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो तो ऐसी संरचना विकसित पेशागत संरचना कहलाती है।

अध्याय
9

कर संरचना
(Tax Structure)

कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है, जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। कर को न चुकाना या कर की चोरी करना कानूनन दंडनीय अपराध है। कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है, जिसे सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिये स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

- 'कर आधार' वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है, जैसे- 'आयकर' में आय आधार होता है।
- कर दो प्रकार का होता है- प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर।

9.1 कर के उद्देश्य *(Purpose of Tax)*

आर्थिक विकास

कर लगाने का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास है। यह मान्य अवधारणा है कि आर्थिक विकास हेतु पूंजीगत निवेश आवश्यक है। सरकार निवेश हेतु धन का प्रबंधन विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों से करती है। कर से प्राप्त आय को सरकारें इच्छानुसार व्यय करती हैं।

मूल्य स्थिरता

कर मुद्रास्फीति प्रबंधन का भी एक बेहतर विकल्प है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर में वृद्धि करके उनकी मांग को प्रभावित किया जा सकता है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिक कर उनकी मांग को हतोत्साहित करता है तथा अन्य क्षेत्रों में खर्च को प्रोत्साहित करता है। उदाहरणस्वरूप निजी वाहनों की खरीद पर ज़्यादा कर इनकी मांग को कम करता है, परंतु सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार निजी खर्च को प्रभावित कर मूल्य स्थिरता बनाए रखी जा सकती है।

हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित करना

सरकारें विभिन्न उपभोग के ऐसे उत्पाद, जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं, के उपयोग को कम करना चाहती हैं। इसके लिये इन उत्पादों पर अधिक कर लगाकर इनके उपभोग को कम किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप एल्कोहल, तंबाकू उत्पादों पर अधिक कर इनके अत्यधिक उपभोग को कम करने में सहायक है।

भुगतान संतुलन से संबंधित मामले

सरकारें विभिन्न विदेशी तथा देशी उत्पादों पर कर लगाकर उनके आयात एवं निर्यात को प्रभावित कर सकती हैं। विदेशी वस्तुओं पर अधिक सीमा शुल्क उनके आयात को हतोत्साहित करता है क्योंकि ये वस्तुएँ अपेक्षाकृत महँगी हो जाती हैं। वस्तुओं पर अधिक कर घरेलू उद्योगों तथा निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

इस प्रकार भुगतान संतुलन से संबंधित मामलों में सरकार आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप कर सकती है।

आय का पुनर्वितरण करने में

सरकारें धनी लोगों पर अधिक कर लगाकर प्राप्त आय को ज़रूरतमंद तथा निर्धन लोगों पर खर्च करती हैं। इसके लिये सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ संचालित करती हैं। इसके अलावा सब्सिडी के माध्यम से भी सरकार

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596